



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 1985/आश्विन 9, 1907
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 1985/ASVINA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विषय: न्यूयार्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश
कीमन द्वारा 22 अगस्त, 1985 को पारित अखंडन
आदेश।

सं. 21/89/85-केम I.—22 अगस्त, 1985 को न्यूयार्क
में भोपाल गैस त्रासदी के मामले की कार्यवाही के संबंध में
न्यायाधीश कीमन द्वारा पारित निम्नलिखित आदेश को एतद्-
द्वारा आम सूचना एवं अनुपालन के लिए प्रकाशित किया जाता
है।

“एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि (1) प्रतिवादी
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इसकी सहायक तथा संबद्ध कंप-
नियां, इसके कर्मचारी तथा इसके न्यायवादी (2) अभिभोगी
भारत संघ, इसके अधिकरण, सहायक तथा राजनैतिक उप-
प्रभाग जिसमें बिना सीमा के वे भी शामिल हैं जिनका भोपाल

संघ के स्थान प्रचालन या विनिर्माण में, उसमें किए जाने वाले
कार्यकलाप में या उसके पर्यावरण में किसी प्रकार का उत्तर-
दायित्व या अन्तर्ग्रस्तता थी तथा बिना किसी सीमा के भारतीय
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित, जिन्होंने घटना की जांच की तथा
(3) व्यक्तिगत दावाकर्ताओं के न्यायवादी किसी भी ऐसे
प्रकार या स्वरूप के दस्तावेज या साक्ष्य को क्षतिग्रस्त,
खंडित या नष्ट नहीं करेंगे जिनका उपर्युक्त मामले से कोई
संभाव्य संबंध हो।

व्यक्तिगत दावाकर्ताओं के प्रत्येक न्यायवादी अपने मुख-
किकल को, तथा यदि लागू हो तो अपने मुखकिकलों के भारतीय
वकील को शीघ्र सूचित करेंगे कि वे और उनके कर्मचारी,
अधिकरण, विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्ति, जिनका संबंध दस्ता-
वेजों या साक्ष्य तक पहुंच है, उनमें से प्रत्येक पर यह आदेश
लागू होता है।

इस आदेश के प्रयोजन के लिए दस्तावेज में प्रत्येक लिखित
सामग्री तथा हर प्रकार के चित्रण का रिकार्ड तथा उनके भी
प्रारंभिक मसौदे, जिनमें ये भी शामिल हैं, परन्तु उन तक ही

सीमित नहीं, डेके, नीनिया, करार, वर्कशीट, पत्राचार, ज्ञापन हस्तलिखित तथा टंकित टिप्पणियां, वक्ताव्य, रिपोर्टें कार्यवृत्त, आलेखन, वीडियो टेप, प्रेस विज्ञापित, समाचारपत्र लेख, बैठकों के प्रतिलेख तथा सारांश, आवाज रिकार्डिंग, पिक्चर, फोटो ग्राफ्स, ड्राइंग कंप्यूटर कार्ड, टेप, डिस्क, सभी प्रकार के प्रिंट आउट तथा रिकार्ड, अध्ययन, पुस्तकें, दृष्टेहार, बीजक, रद्द चैक तथा अन्य ऐसे सभी माध्यम या माध्यम जिनके जरिये सूचना संप्रेषित, रिकार्ड या परिरक्षित की जाती है।

दस्तावेज का परिभाषा में ऐसी प्रतिलिपि भी शामिल है जिसकी मूल प्रति यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, भारत संघ व्यक्तिगत जादियों या दवाकर्ताओं या उनकी न्यायवाधियों के स्वामित्व में नहीं हैं तथा किसी भी दस्तावेज का प्रत्येक प्रति यदि ऐसी प्रति मूल प्रति के समान दूसरी प्रति न हो।

अन्य संबंध दस्तावेजों में, किसी भी दस्तावेज को इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस कार्यवाही से संबंध माना जाएगा यदि यह किसी भी प्रकार से भोपाल संघ के लिए स्थान के चयन तथा यूनिट की व्यवस्था, इसके डिजाइन, प्रोसेस प्लो डायग्राम प्रोसेस एवं इंस्ट्रुमेंट डायग्राम, निष्पादन विशिष्टताओं और सभी मुख्य तथा लघु उपस्कर के निर्माण की सामग्री, निष्पादन (सभी सुरक्षा तथा प्रचालन नियम पुस्तिकाओं, सहित), निर्माण विशिष्टताओं का वास्तव पाईपिंग सामग्री, डिजाइनमापदण्ड तथा यूनियन कार्बाइड के स्वामित्व वाले उपस्करों के खाके, गहन उपस्कर व्यवस्था तथा यूनिट ले आउट तथा विशेष विश्लेषणात्मक इंस्ट्रुमेंटेशन तथा प्रयोगशाला क्वालिटी नियंत्रण उपस्कर के विवरण से संबंध हो। उन दस्तावेजों को भी इस मामले से संबंध समझा जाएगा चाहे वे भोपाल संघ से संबंधित हों या यूनियन कार्बाइड के अन्य किस सुविधा से सम्बद्ध हो, जैसा कि एक संस्थान वेस्ट विरजिनिया में है।

किसी भी ऐसे दस्तावेज को इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस कार्यवाही से संबंध समझा जाएगा, यदि यह किसी भी तरह से भोपाल संघ में सरकार की अंतर्ग्रस्तता या विनियमन से संबंध हो, जिसमें, बिना किसी सीमा के, इसका निर्माण, निर्माण उपस्कर की सामग्री, ठेकेदार और डिजाइनर, इसके संचालन, सरकार के किसी भी कानून या विनियमनों के संबंध में इस के अनुपालन, इसकी खलीकित तथा इसके स्थान चयन तथा संयंत्र के आसपास विकास तथा जनसंख्या शामिल है।

इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस कार्यवाही से ऐसे दस्तावेज को भी सम्बद्ध समझा जाएगा, यदि यह किसी भी तरह से किसी व्यक्ति मृदुई या दावेदारों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित दावों, मृत्यु डाक्टरी इलाज और स्थिति (दिसंबर 3, 1984 से पहले की स्थिति सहित) डाक्टरी व्यय, कमाई या अन्य आय, शिक्षा, नियोजन जीवनांक (आयु तथा लिंग सहित) या क्षतियों के दावों से संबंधित हों। दस्तावेजों को संबंध समझा जाएगा चाहे वे इस आदेश के अध्याधून दिसंबर,

3, 1984 से पहले या दिसंबर 3, 1984 के बाद, जैसे कि इस घटना की जांच पड़ताल के दौरान उनके स्वामित्व संरक्षण या नियंत्रण में आए हों।

इस आदेश की प्राप्ति पर यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन अपने उन सभी न्यायवाधियों (न्यायवाधियों के सभी कर्मचारियों सहित), कर्मचारियों, एजेंटों, विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों को शीघ्र सूचित करने के लिए उचित उपाय करेगी जिनके पास अब उपर्युक्त दस्तावेजों या साक्ष्य में से कोई भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, भारत संघ मध्य प्रदेश राज्य सरकार, और भोपाल की नगरपालिकाओं, उनके प्रतिनिधियों और अधिकारियों और कर्मचारियों, उनके न्यायवाधियों तथा उनके अभिकरणों, सहायकों तथा राजनैतिक उप प्रभागों, बिना सीमा के उनके सहित जिनकी भोपाल संघ के स्थान-निर्धारण प्रचालन या विनियमन में या उसके अन्दर किए जाने वाले कार्यकलापों या उसके घेरे में अंतर्ग्रस्तता हों तथा उन्हें, बिना किसी सीमा के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्थापित-जांच आयोग सहित, जिन्होंने घटना की जांच की है, से इस आदेश की शर्तों के स्वैच्छिक अनुपालन प्राप्त करने के लिए शीघ्र उचित प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, भारत संघ तथा अलग-अलग दवाकर्ताओं के न्यायवादी इस आदेश के पैंतालिस (45) दिनों के अन्दर न्यायालय को सभी दस्तावेजों या साक्ष्यों की सूची देंगे, यदि कोई हो तो, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है तथा जो दिसंबर 2, 1984 से क्षतिग्रस्त हो गए, कट-फट गए या खो गए। ऐसी सूचना, यथासंभव सीमा तक उन दस्तावेजों या साक्ष्य की शिनाख्त करेगी जो क्षतिग्रस्त हुए या खो गए तथा उनके क्षतिग्रस्त हो जाने या खो जाने के कारण बतायेंगी। यदि इस आदेश के कार्यक्षेत्र में आने वाले दस्तावेजों या साक्ष्य को इसके बाध नष्ट किया जाता है या खो दिया जाता है तो यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, भारत संघ, या अलग-अलग दवाकर्ताओं के न्यायवादी जैसी भी स्थिति हो, तत्काल न्यायालय को लिखित में सूचित करेंगे, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है।

इस आदेश के अनुपालन में विफलता की स्थिति में फेडरल रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर के नियम 37 के अनुसार दंड दिया जाएगा।

ऐसा आदेश दिया जाता है।

दिनांक : न्यूयॉर्क, न्यूयार्क,

अगस्त, 22, 1985

ह/-

जान एफ. कीनन,

यू. एस. डी. जे.

प्रामाण्य घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 27th September, 1985

NOTIFICATION

Subject :—Non-destruct Order passed by Justice Keenan of the South District Court of New York on 22nd August, 1985.

No. 21/89/85-CH.I.—The following Order passed by Justice Keenan in connection with the proceedings of the Bhopal Gas Tragedy case in New York on 22nd August, 1985 is hereby published for general information and compliance:

“It is hereby ordered that (1) Defendant Union Carbide Corporation, its subsidiaries and affiliates, its employees and its attorneys, (2) Plaintiff the Union of India, its Agencies, instrumentalities and political subdivisions, including without limitation those that had any responsibilities for or involvement in the location, operation or regulation of the Bhopal Plant, the activities conducted therein or its environs and those including without limitation the Indian Central Bureau of Investigation, that have investigated the incident, and (3) the attorneys for individual claimants shall not damage, mutilate or destroy any document or evidence of any kind or nature having potential relevance to the above-captioned matter.

Each attorney for individual claimants shall promptly notify his clients, and if applicable Indian Counsel for his clients, that they and their employees, agents, experts and other persons who have access to relevant documents or evidence are each subject to this Order.

For purposes of this Order ‘Document’ shall include every writing and record of every type and description and all preliminary drafts thereof, including but not limited to, contracts, policies, agreements, worksheets, correspondence, memoranda, handwritten and typed notes, statements, reports, minutes, recordings, videotapes, press release, newspaper articles, transcripts and summaries of meetings, voice recordings, pictures, photographs, drawings, computer cards, tapes, discs, printouts and records of all types, studies, books, pamphlets, invoices, cancelled checks, and every other device or medium by which or through which information is transmitted, recorded or preserved.

The term document also encompasses a copy where the original is not in the possession, custody or control of Union Carbide Corporation, the Union of India, the individual plaintiffs or claimants or their attorneys and every copy of any document if such copy is not an identical duplicate of the original.

Among other relevant documents, a document is deemed to be of relevance to this action for the purpose of this order, if it, in any way, relates to site

selection and unit layout of the Bhopal plant, its design, process flow diagrams, process and instrument diagrams, performance specifications and materials of construction of all major and minor equipment, performance including all safety and operational manuals, valve piping materials of construction specifications, design criteria and sketches of Union Carbide's proprietary equipment, typical equipment arrangements and unit layout, and description of special analytical instrumentation and laboratory quality control equipment.

Documents shall be deemed relevant matter whether they relate to the Bhopal plant or any other similar Union Carbide Facility, such as the one in institute, West Virginia.

A document is also deemed to be of relevance to this action for the purposes of this order, if it in any way relates to any Government involvement with or regulation of the Bhopal Plant, including, without limitation, its construction, materials of construction equipments, contractors and designers, its operation, its compliance with any Governmental laws or regulations, its siting and its site selection and the development and population around the plant.

A document is also deemed to be relevance to this action for the purpose of this Order, if it, in any way, relates to the death, medical treatment and condition (including prior to December 3, 1984), medical expenses earnings or other income, education, employment, vital statistics (including age and sex) or claims for damages of any individual plaintiffs or claimants or their decedents.

Documents shall be deemed relevant whether they came into the procession, custody or control of those subject to this order prior to December 3, 1984, or after December 3, 1984 such as in the course of the investigation of the incident.

Upon receipt of this Order, Union Carbide Corporation shall promptly make reasonable efforts to notify all its attorneys (including all employees of attorneys), employees agents, experts and other persons who now have access to any of the afore-described documents or evidence.

Further the Union of India shall promptly make reasonable efforts to obtain the voluntary compliance with the terms of this order by the State of Madhya Pradesh and the Municipality of Bhopal, their representatives, officials and employees, their attorneys and their agencies, instrumentalities and political subdivisions, including without limitation those that had any responsibilities for or involvement in the location, operation or regulation of the Bhopal involvement in the location, operation or regulation of the Bhopal plant or the activities conducted therein or

its environs and those, including without limitation the commission of enquiry established by the State of Madhya Pradesh, that have investigated the incident further, Union Carbide Corporation, the Union of India and the Attorneys for the individual claimants shall provide the court within forty-five (45) days of this order with a listing of all documents or evidence, if any, referred to here in which have been damaged, mutilated, destroyed or lost since December 2, 1984. Such notice, to the extent possible shall identify the documents or evidence destroyed or lost and state the reason for their destruction or loss. In the event documents or evidence within the scope of this order are hereafter destroyed or lost, Union Carbide Corporation, the Union of India or the attorney for the individual claimants, as the case may

be, shall immediately notify the court in writing, as specified above.

A failure to comply with this order shall be subject to sanctions pursuant to Rule 37 of the Federal Rules of Civil Procedure.

So ordered.

Dated : New Yor, New York

August 22, 1985.

Sd/-

JOHN F. KEENAN

U.S.D.J.

SHYAMAL GHOSH, Jt. Secy.